खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा धन-राशि की मांग

1556. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग के विकास और संचालन के लिए 8,000 करोड़ रुपये की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने खादी उद्योग के विकास के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समयबद्ध लक्ष्य क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिए 6,300 करोड़ रु० की मांग की है।

(ख) से (घ) सरकार का प्रयास खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा उसकी संस्थाओं के माध्यम से खादी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने तथा उसे विकसित करने का रहा है। इस दिशा में समय समय पर कई उपाय किये हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) खादी उद्योगों के प्रोत्साहन तथा पोषण के लिए सस्ती, सुगम तथा व्यापक सहायता की व्यवस्था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के कमजोर तथा असुरक्षित वर्गों को लाभ पहुंचे।

(2) गुणवत्ता तथा मात्रा की दृष्टि से सूती खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च गति के छः तकुओं वाले नये माडल चर्खे और ग्राम लक्ष्मी कर्घे शुरू करना।

(3) डी.आर.डी.ए. के सक्रिय सहयोग से गहन खादी उत्पादन तथा रोजगार सृजन योजना देश के भिन्न-भिन्न भागों में शुरू की गई है।

(4) कातने वालों को नियमित तथा बढ़िया कच्चा माल सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सिल्वर संयंत्र स्थापित करना।

(5) चरखों के बेकार पड़े रहने से बचने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में नये मॉडल के चरखों हेतु स्पेयर पार्ट के भण्डारण एवं आपूर्ति हेतु सुविधाओं का विस्तार करना।

(6) के.वी.आई. उत्पादों के लिये मार्ग प्रशस्त करने के लिए नाबार्ड और सिडबी की वित्तीय सहायता से नये खादी भण्डार/भवन स्थापित करना ताकि उत्पाद उपभोक्ता के घरों तक पहुंच सके।

(7) नयी संस्थाओं को सूचीबद्ध करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना, रुग्ण तथा समस्याग्रस्त संस्थाओं को पुनः चालू करना और सक्रिय समन्वय हेतु राज्य स्तरीय सघों का गठन करना आदि।

इसके अलावा, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, खादी उत्पाद विकास केन्द्रों, परिधान उत्पादन केन्द्रों तथा खादी निर्यातोन्मुख एककों का विकास शुरू करने का प्रस्ताव है।

इन योजनाओं के 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किये जाने की आशा है।

भारी उद्योग विभाग के प्रबंधाधीन उपक्रम

1557. **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, भारी उद्योग विभाग द्वारा कुल कितने उपक्रमों का प्रबन्ध किया जा रहा है ;